

संपादकीय

वायु सेना की रक्षा परियोजनाओं में देरी क्यों?

भारतीय वायुसेना प्रमुख ने 29 मई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक सभा में रक्षा परियोजनाओं में देरी को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा, “टाइमलाइन एक बड़ा मुद्दा है। मेरे विचार में एक भी परियोजना ऐसी नहीं है जो समय पर पूरी हुई हो। कई बार हम कांट्रैक्ट साइन करते समय जानते हैं कि यह सिस्टम समय पर नहीं आएगा, फिर भी हम कांट्रैक्ट साइन कर लेते हैं।” यह बयान न केवल रक्षा क्षेत्र में मौजूदा चुनौतियों को उजागर करता है, बल्कि भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में चल रही प्रक्रिया पर भी सवाल उठाता है। एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने अपने बयान में विशेष रूप से हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच.ए.एल.) द्वारा तेजस एम.के.1ए फाइटर जेट की डिलीवरी में देरी का उल्लेख किया। यह देरी 2021 में हस्ताक्षरित 48,000 करोड़ रुपये के कांट्रैक्ट का हिस्सा है, जिसमें 83 तेजस एम.के.1ए जैट्स की डिलीवरी मार्च 2024 से शुरू होनी थी, लेकिन अभी तक एक भी विमान डिलीवर नहीं हुआ है।

इसके अलावा, उन्होंने तेजस एम.के.2 और उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (ए.एम.सी.ए.) जैसे अन्य महत्वपूर्ण प्रोजैक्ट्स में भी प्रोटोटाइप की कमी और देरी का जिक्र किया। यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है, विशेष रूप से ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद, जिसे उन्होंने ‘राष्ट्रीय जीत’ करार दिया। उनके बयान का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह रक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता को रेखांकित करता है। यह पहली बार नहीं है जब एच.ए.एल. की आलोचना हुई है। फरवरी 2025 में, एयरो इंडिया 2025 के दौरान, एयर चीफ मार्शल सिंह ने एच.ए.एल. के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा था, कि मुझे एच.ए.एल. पर भरोसा नहीं है, जो बहुत गलत बात है। यह बयान एक अनौपचारिक बातचीत में रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन इसने रक्षा उद्योग में गहरी मुद्दों को उजागर किया।

रक्षा परियोजनाओं में देरी के कई कारण हैं, जिनमें से कुछ संरचनात्मक और कुछ प्रबंधन से संबंधित हैं। तेजस एम.के.1ए की डिलीवरी में देरी का एक प्रमुख कारण जनरल इलैक्ट्रिक से इंजनों की धीमी आपूर्ति है। वैश्विक आपूर्ति शृंखला में समस्याएं, विशेष रूप से 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद भारत पर लगाे प्रतिबंधों ने एच.ए.एल. की उत्पादन क्षमता को प्रभावित किया है। सिंह ने एच.ए.एल. के ‘मिशन मोड’ में न होने के लिए आलोचना की। उन्होंने कहा कि एच.ए.एल. के भीतर लोग अपने-अपने साइलो में काम करते हैं, जिससे समग्र तस्वीर पर ध्यान नहीं दिया जाता। यह संगठनात्मक अक्षमता और समन्वय की कमी का संकेत है। सिंह ने इस बात पर भी जोर दिया कि कई बार कांट्रैक्ट साइन करते समय ही यह स्पष्ट हो जाता है कि समय सीमा अवास्तविक है। फिर भी, कांट्रैक्ट साइन कर लिए जाते हैं, जिससे प्रक्रिया शुरू से ही खराब हो जाती है।

रक्षा कांट्रैक्ट्स में यथार्थवादी समय सीमाएं निर्धारित की जानी चाहिए। सिंह ने सुझाव दिया कि हमें वही वायदा करना चाहिए जो हम हासिल कर सकते हैं। इसके लिए एंस्ट्रैक्ट साइन करने से पहले गहन तकनीकी और लॉजिस्टिकल मूल्यांकन की आवश्यकता है। ए.एम.सी.ए. प्रोजैक्ट में निजी क्षेत्र की भागीदारी एक सकारात्मक कदम है। निजी कंपनियों को रक्षा उत्पादन में और अधिक शामिल करने से एच.ए.एल. और डी.आर.डी.ओ. पर निर्भरता कम होगी और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह का बयान रक्षा क्षेत्र में गहरी जड़ें जमाए बैठी समस्याओं को उजागर करता है। उनकी स्पष्टवादिता न केवल जवाबदेही को मांग करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि भारत को आत्मनिर्भर और युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए तत्काल सुधारों का आवश्यकता है।

भारतीय सैन्य रणनीति की जरूरत है थियेटर कमान

हरीश शिवनांनी
अन्ततः भारत ने सैन्य क्षेत्र में थियेटर कमान की स्थापना और थियेटर कमांडर की नियुक्ति करने का महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया। ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन के बाद रक्षा बजट में वृद्धि के प्रस्ताव और पांचवीं पीढ़ी के आक्रामक गहराई से भेदने वाले अत्याधुनिक लड़ाकू विमान एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट परियोजना को मंजूरी देने के साथ यह एक सामयिक सामरिक निर्णय है। बदलते भू-राजनैतिक परिदृश्य और भारत की सीमाओं के पास पसरे सुरजुओं के अतीत और इरादों को देखते हुए यह कदम पहले ही उठाने की जरूरत थी। सरकार ने डेढ़ वर्ष से लंबित थियेटर कमान के गठन की जमीनी तैयारियों का क्रियान्वयन शुरू कर दिया है। केंद्र ने अंतर सेवा संगठन अधिनियम (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) यानी (इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन (कमांड, कंट्रोल एंड डिस्पिनिन एक्ट 2023) बुधवार को राजपत्र में अधिसूचित कर दिया। यह थियेटर कमान के गठन का प्रथम चरण है। जाहिर है,ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद केंद्र सरकार ने अपनी रक्षा तैयारियों को और मजबूती प्रदान करनी शुरू कर दी है। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने सेनाओं की दक्षता बढ़ाने के लिए? थियेटर कमान के गठन का निर्णय पहले कर लिया था। इसके तहत भारतीय सशस्त्र सेनाओं की तीनों सेवाओं की ऐसी कमानें गठित होंगी, जिसमें थल,नभ,जल सेना सहित अर्धसैनिक बलों को भी शामिल किया जा सकता है। यह लंबे समय से प्रतीक्षित सामरिक महत्व का सुधार है जो भविष्य के युद्धों को लड़ने के

जाहिर है,ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद केंद्र सरकार ने अपनी रक्षा तैयारियों को और मजबूती प्रदान करनी शुरू कर दी है। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने सेनाओं की दक्षता बढ़ाने के लिए? थियेटर कमान के गठन का निर्णय पहले कर लिया था। इसके तहत भारतीय सशस्त्र सेनाओं की तीनों सेवाओं की ऐसी कमानें गठित होंगी, जिसमें थल,नभ,जल सेना सहित अर्धसैनिक बलों को भी शामिल किया जा सकता है। यह लंबे समय से प्रतीक्षित सामरिक महत्व का सुधार है जो भविष्य के युद्धों को लड़ने के लिए सैन्य संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए है।

लिए सैन्य संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए है। संसद से 2023 को पारित इस अधिनियम को इसी 27 मई को सरकार ने भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया है। इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य एक निश्चित भौगोलिक इकाई में सेना के तीनों अंगों के एक समूह को प्रभावी कमांड, सटीक नियंत्रण और कुशल कामकाज को बढ़ावा देना है, जिससे सशस्त्र बलों के बीच तालमेल बेहतर होगा। यह अधिनियम आईएसओ के कमांडर-इन-चीफ और ऑफिसर-इन-कमांड को मजबूत और प्रभावी बनाएगा। दरअसल थियेटर कमान का अर्थ है एक क्षेत्रीय इकाई में सेना, नौसेना और वायु सेना के समन्वित संचालन के लिए एक ही कमांडर के अधीन एकीकृत करना। यह एक ऐसी सैन्य संरचना है, जो विभिन्न सैन्य शाखाओं के बीच समन्वय और दक्षता को बढ़ाएगी। सैन्य क्षेत्र में थिएटर कमान में थियेटर का मतलब एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से है, जहां सैन्य अभियान या ऑपरेशन किए जाते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां युद्ध, सैन्य रणनीति, या सुरक्षा से संबंधित गतिविधियां केंद्रित होती हैं। थियेटर शब्द का उपयोग सैन्य संदर्भ में इसलिए

चर

दशक से ज्यादा समय तक नक्सलवाद का शिकार रहे छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले को अब वामपंथी उग्रवादियों (एलडब्ल्यूई) जिले की सूची से बाहर कर दिया गया है। अपने आप में ये बड़ी खबर है। दरअसल नरेन्द्र मोदी सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक भारत पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो जाए। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी कई बार सार्वजनिक मंच से इस बात को दोहरा चुके हैं। शाह अगस्त 2024 और दिसंबर 2024 में छत्तीसगढ़ के रायपुर और जगदलपुर में अलग-अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने अलग-अलग मंचों से नक्सलियों को चेताते हुए कहा था कि हथियार डाल दें। हिंसा करोगे तो हमारे जवान निपटेंगे। उन्होंने एक डेडलाइन भी जारी की थी कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद का ख़ात्मा कर दिया जाएगा। शाह के डेडलाइन जारी करने के बाद से बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन काफी तेज हो गए हैं।

नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई है। इसकी शुरुआत स्थानीय जमींदारों के खिलाफ विद्रोह के रूप में हुई, जिन्होंने भूमि विवाद को लेकर एक किसान को पिटाई की थी। यह आंदोलन जल्द ही पूर्वी भारत के छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे कम विकसित क्षेत्रों में फैल गया। वामपंथी उग्रवादियों (एलडब्ल्यूई) को दुनिया भर में माओवादी और भारत में नक्सलवाद के नाम से जाना जाता है। वे सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत सरकार को उखाड़ फेंकने और माओवादी सिद्धांतों पर आधारित साम्यवादी राज्य की स्थापना की वकालत करते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल राज्यों को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित माना जाता है।

देश में भाजपा सरकार बनने के बाद 2015 में नक्सलवाद के खिलाफ विशेष अभियान चलाने की नीति बनाई गई। तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आठ सूत्री समाधान एक्शन प्लान बनाया। इसमें नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई और नक्सली इलाकों में विकास के काम एक



साथ किए गए। नक्सलियों के खिलाफ राज्य सरकारों के विशेष बल, केंद्रीय सुरक्षा बलों, पुलिस ने मिलकर कार्रवाई की। इससे नक्सली घटनाओं में जबरदस्त कमी आयी 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जिसे भारत की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती कहा था, वही नक्सलवाद अब खत्म होता दिख रहा है। नक्सलियों ने नेपाल के पशुपति से आंध्र प्रदेश के तिरुपति तक एक रेड कॉरिडोर स्थापित करने की योजना बनाई थी। 2013 में लगभग 126 जिलों में नक्सली सक्रिय थे। वर्तमान में नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर 6 हो गई। इनमें छत्तीसगढ़ के चार जिले–बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा, झारखंड का एक जिला– पश्चिमी सिंहभूम और महाराष्ट्र का एक जिला– गढ़चिरोली शामिल है।

वर्ष 2025 में सुरक्षाबलों के ऑपरेशन में अब तक 287 नक्सली मारे जा चुके हैं। वहीं 865 ने समर्पण किया है और 830 गिरफ्तार हुए हैं। गत 21 मई को सुरक्षाबलों ने अबूझमाड़ में डेढ़ करोड़ के इनामी नंबला केशव उर्फ बसवराज को मार गिराया। वह तीन दशक से सक्रिय था। इसे नक्सलियों का हाफिज सईद भी कहा जाता है। नक्सलियों के सरदार बसवा राजू के ढेर होने के बाद माओवादियों का हौसला पस्त हो गया है। इस बड़े एनकाउंटर के बाद दक्षिण बस्तर डिवीजन में चार हार्डकोर नक्सलियों सहित 18 माओवादियों ने सरेंडर किया था। इसी तरह बीजापुर में 32 और तेलंगाना में 86 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। बासव राजू की मौत के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर लिखा था कि महासचिव स्तर के बड़े नक्सली

काम करती हैं, ताकि उस क्षेत्र में सैन्य रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। कमान का सर्वोच्च अधिकारी थियेटर कमांडर होता है जो एक सैन्य अधिकारी होता है, जो एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र (थियेटर ऑफ ऑपरेशन) में सैन्य अभियानों का नेतृत्व करता है। और उस क्षेत्र में सभी सैन्य बलों (सेना, नौसेना, वायुसेना) के संचालन को समन्वयित करता है। यह एक परिचालन कमांडर की (ऑपरेशनल) भूमिका है, जो युद्ध या संकट के दौरान रणनीति और कमान को लागू करती है।

इन कमानों के लिए चुने गए थियेटर कमांडर सामान्य रूप से थलसेना से लेफ्टिनेंट जनरल, नौसेना से वाइस एडमिरल या वायुसेना से एयर मार्शल स्तर का अधिकारी हो सकता है, जिसे कमांड की जिम्मेदारी दी जाएगी। यह एक एग्रीक्यूटिव पद है, जो विशिष्ट थियेटर के लिए ही गठित होगी, स्थायी नहीं। पहले के सशस्त्र बलों के कानूनी ढांचे में त्रि-सेवा मामलों में निश्चित विधिक सीमाएं निर्धारित थीं, क्योंकि एक सेवा के अधिकारी को दूसरी सेवा के कर्मियों पर अनुशासनात्मक और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार नहीं था। उदाहरण के लिए, एक संयुक्त कमांड का नेतृत्व करने वाला तीन-सितारा जनरल अपने अधीन सेवा करने वाले वायुसेना या नौसेना कर्मियों न कोई निर्देश दे सकता था न ही उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता था। ऐसी शक्तियों की कमी का कमांड, नियंत्रण और अनुशासन पर सीधा प्रभाव पड़ता था। थियेटर कमानों की स्थापना से अब स्थिति बदल जाएगी। थियेटराइजेशन अभियान का नेतृत्व रक्षा स्टाफ के प्रमुख (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान कर रहे हैं।

आजकल

स्कूल में पढ़ने की उम्र में बढ़ता जुर्म

हिसार में सहपाठी द्वारा प्रतिशोध में कक्षा दस के एक छात्र की गोली मारकर की गई हत्या ने हर संवेदनशील व्यक्ति को झकझोरा है। एक साल पहले स्कूल में डेस्क पर बैठने को लेकर विवाद की खूंढक आरोपी छात्र अपने दिमाग में पालता-पोसता रहा। फिर एक दिन सहपाठी को सुबह मिलने के बहाने बुलाया और अपने दादा के हथियार से गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बेहद दुखद है और हर मां-बाप के लिये बेहद चिंता का विषय कि उनके बच्चे का सहपाठी भी इतना खूंखार हो सकता है। हमारे जिस समाज की प्यार, सामंजस्य व सहयोग के लिये मिसाल दी जाती थी, उसमें ये किशोर आखिर ऐसा भयानक कदम कैसे उठा रहे हैं? जिस उम्र में किशोरों को पढ़ना-लिखना था, उस समय में वे हिंसक गतिविधियों में क्यों लिस हो रहे हैं? दोषी तो आरोपी छात्र के अधिभावक भी हैं कि जिन्होंने घातक हथियार को लापरवाही से घर में छोड़ा, जिससे आरोपी ने हत्या को अंजाम दिया। बताते हैं कि आरोपी छात्र के दादा सेना से सेवानिवृत्त हैं और एक बैंक में सुरक्षा गार्ड हैं।

कितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि मृतक छात्र अपने परिवार में इकलौता था और अपने परिवार को हमेशा के लिये रोता-बिलखता छोड़ गया। एक समय अमेरिका व यूरोप में ऐसी घटनाएं सुनने में आती थी। अब ये किशोर अपराध हमारे दरवाजों पर भी दस्तक देने लगे हैं। समाज में व्याप्त नकारात्मकता व हिंसक प्रवृत्ति का किशोरों द्वारा अनुकरण करना हमारे समाज के लिये ख़रबे की घंटी ही है।

बीते मार्च में दिल्ली के वजीराबाद इलाके में एक छात्र की ऐसी ही निर्मम हत्या हुई थी। वजीराबाद की घटना में एक नौवीं के छात्र का अपहरण करके उसके परिजनों से दस लाख की फिरोती मांगी गई थी। छात्र की हत्या के बाद जांच में पता चला कि उसके अपहरण व हत्या में तीन किशोर संलिप्त थे। आए दिन स्कूल-कालेज विवाद में हिंसक घटनाएं हमें परेशान करती हैं। यदि कम उम्र के बच्चों व किशोरों में बढ़ती हिंसक प्रतिशोध की प्रवृत्ति पर लगाम न लगी तो डर लगता है कि आने वाले समय में हमारे समाज का स्वरूप कैसे होगा। सवाल यह है कि आखिर किशोरों में अपराधिक प्रवृत्तियां क्यों पनप रही हैं।

साधन के बारे में जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 03 जून को

विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 03 जून को यह दिवस मनाने की घोषणा साइकिल सवारी से मिलने वाले स्वास्थ्य, पर्यावरण और आवागमन के लिए सबसे सस्ता साधन इत्यादि को देखते हुए की थी। दरअसल साइकिल का महत्व धीरे-धीरे घटता जा रहा था, तकनीक के विकास के साथ ही पेट्रोल-डीजल इत्यादि से चलने वाली गाड़ियों का उपयोग बढ़ने लगा और लोगों ने समय की बचत तथा सुविधा के लिए साइकिल चलाना बेहद कम कर दिया। इसीलिए साइकिल के उपयोग और जरूरत के बारे में बच्चों और अन्य लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से संयुक्त

है और भारत साइकिल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है।

साइकिल पर्यावरण के लिए यातायात का सबसे उत्तम साधन है क्योंकि इसके उपयोग से डीजल-पेट्रोल का दोहन कम होने के साथ ही प्रदूषण स्तर भी कम होता है। साथ ही शरीर को स्वस्थ रखने में भी साइकिल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साइकिल चलाने से न केवल पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है बल्कि यह व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास में भी सहायक होता है। यही कारण है कि साइकिल की विविधता, मौलिकता और परिवहन के एक व्यापक और सहज

भी साइकिलों का उपयोग बढ़ रहा है। भारत का साइकिल उद्योग आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार

सफर और अच्छे सेहत की साथी...

यूरोप, डेनमार्क, नीदरलैंड इत्यादि दुनिया के कई हिस्से आज भी ऐसे हैं, जहां साइकिल के जरिये ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया जाता है। साइकिल का दौर 1960 से लेकर 1990 के बीच काफी अच्छा चला लेकिन उसके बाद समय

बदलता गया और साइकिल का चलन भी कम होता गया। बीते कुछ वर्षों में पर्यावण की महत्ता और साइकिल चलाने से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी लाभ को देखते हुए लोग साइकिल की ओर आकर्षित हुए हैं और यही कारण है कि अब केवल भारत ही नहीं बल्कि जापान, इंग्लैंड सहित कई विकसित देशों में



वाले, स्कूल जाने वाले छात्र इत्यादि ही साइकिल पर दिखते थे। साइकिल की कीमत तब ज्यादा नहीं होती थी और प्रायः एक ही जैसी साइकिलें बाजार में मिलती थी लेकिन समय के साथ बदलती तकनीक के दौर में साइकिलें भी हाईटेक होती गईं और आज बाजार में कुछ हजार से लेकर लाखों रुपये तक की साइकिलें उपलब्ध हैं।

समय के साथ साइकिल की उपयोगिता और महत्व भी बदलता गया है और आज के आधुनिक दौर में साइकिलें अधिकांशतः व्या्याम अथवा शारीरिक फिटनेस के तौर पर प्रयोग की जाती हैं। आज के जमाने में लोग घंटों साइकिल चालकर इससे सेहत और वातावरण को पहुंचने वाले फायदों के बारे में जागरुकता फैलाते हैं। हालांकि